This question paper contains 8+3 printed pages]

Your Roll No. .....

6368

LL.B./IV Term **A**

Paper LB-402—ADMINISTRATIVE LAW

Time : 3 *Hours* *Maximum Marks* : 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note :— Answers may be written *either* in English *or* in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी **या** हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

Attempt *Five* questions, including

Question No. **1** which is compulsory.

All questions carry equal marks.

अनिवार्य प्रश्न क्रमांक **1** सहित

कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

P.T.O.

1. Explain briefly any *four* of the following :

   (*i*) Principle of proportionality;

   (*ii*) Laying of delegated legislation;

   (*iii*) Commission of Enquiry;

   (*iv*) Right to cross-examination;

   (*v*) Curative petition. 20

   निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** के उत्तर संक्षेप में लिखिए :

   (*i*) समानुपातिकता का सिद्धान्त;

   (*ii*) प्रत्यायोजित विधान का रखा जाना;

   (*iii*) जाँच आयोग;

   (*iv*) प्रति-परीक्षा करने का अधिकार

   (*v*) सुधारात्मक याचिका।

2. (*a*) Discuss the permissible limits of delegation of law making power with the help of decided cases.

   (*b*) Explain whether the power to amend or repeal an enactment is a valid delegation of power. 20

(*a*) विनिश्चित केसों की सहायता से विधि निर्माण करने के अधिकार के प्रत्यायोजन की अनुज्ञेय सीमाओं का विवेचन कीजिए।

(*b*) स्पष्ट कीजिए कि क्या किसी अधिनियम को संशोधित अथवा निरसित करने की शक्ति, शक्ति का विधिमान्य प्रत्यायोजन है।

3. (*a*) The Government decided not to refer an industrial dispute relating to non-payment of bonus, as the employees resorted to go slow tactics in the concerned year. Decide whether there is proper exercise of discretion by the government or not.

(*b*) X, a member of a departmental promotion committee, and himself being a candidate for the post-participated in the deliberations for selection of all candidates including 'Y'. He withdrew himself when his name was considered by

the committee. 'X' name was at the top of the list of selected candidates. 'Y' who was not selected for the post challenged the selections. Decide with the help of Judical decisions. 20

(*a*) सरकार ने बोनस की गैर-अदायगी से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद को निर्दिष्ट नहीं करने का निर्णय किया क्योंकि सम्बन्धित वर्ष में कर्मचारियों ने 'धीरे काम करो' के हथकंडे अपनाए थे। विनिश्चय कीजिए कि क्या सरकार द्वारा विवेकाधिकार का उचित प्रयोग किया गया था अथवा नहीं।

(*b*) विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य तथा सम्बन्धित पद के लिए स्वयं अभ्यर्थी X ने Y सहित सभी अभ्यर्थियों के चयन हेतु विमर्शों में भाग लिया था। जब समिति द्वारा उसके नाम पर विचार किया गया था तब वह स्वयं समिति से हट गया था। X का नाम चयनित अभ्यर्थियों

की सूची में शीर्ष पर था। उक्त पद के लिए चयनित नहीं हुए अभ्यर्थी Y ने चयनों को आक्षेपित किया। न्यायिक विनिश्चयों की सहायता से विनिश्चय कीजिए।

4. (*a*) Discuss the salient features of Right to Information Act, 2005.

(*b*) Can the information relating to disclosure of assets by the individual judges to Chief Justice of India be obtained under the Right to Information Act. Refer to judicial decisions. 20

(*a*) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए।

(*b*) क्या सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अलग-अलग न्यायाधीशों द्वारा दी गई परिसम्पत्तियों के प्रकटन सम्बन्धी सूचना को प्राप्त किया जा सकता है ? न्यायिक विनिश्चयों का हवाला दीजिए।

5. (*a*) 'X', a company secretary in a Government company was dismissed from service after conducting an enquiry. The company was represented by its Personnel Manager, who was a legally qualified person. 'X' was not allowed to take the services of lawyer. On the ground that he is Senior Executive and can defend himself. 'X' challenged the proceedings. Decide with the help of decided cases.

(*b*) The Government had the power of granting exemption in tax to newly made and expanded factories of sugar upto 3 years in the State of Uttar Pradesh. The Government makes a policy to grant exemption to newly made factories in cooperative sector, for one year. The other sugar factories in the state challenged that Government should consider every application and cannot lay down a policy to exempt only cooperative sectors. Decide. Refer to judicial decisions. 20

(*a*) किसी सरकारी कम्पनी के कम्पनी सचिव X को जाँच किए जाने के बाद सेवा से बरखास्त कर दिया गया था। कम्पनी का प्रतिनिधित्व इसके कार्मिक प्रबन्धक ने किया था जो विधि में अर्हताप्राप्त व्यक्ति था। X को इस आधार पर किसी वकील की सेवा लेने की अनुमति नहीं दी गई कि वह एक सीनियर एक्जीक्यूटिव था तथा स्वयं का बचाव कर सकता था। X ने कार्यवाहियों को आक्षेपित कर दिया। विनिश्चित केसों की सहायता से विनिश्चय कीजिए।

(*b*) उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार को चीनी की नई लगाई गई तथा विस्तारित की गई फैक्टरियों को कर में तीन वर्ष तक की छूट मंजूर करने की शक्ति प्राप्त है। सरकार ने सहकारी क्षेत्र में नई लगाई गई फैक्टरियों को एक वर्ष के लिए छूट प्रदान करने की नीति बनाई। राज्य की अन्य चीनी फैक्टरियों ने आक्षेप किया कि सरकार को

प्रत्येक अर्जी पर विचार करना चाहिए। सरकार केवल सहकारी क्षेत्र में छूट देने की नीति नहीं बना सकती है। विनिश्चय कीजिए। न्यायिक विनिश्चयों का हवाला दीजिए।

6. (*a*) Discuss the constitutional validity of Articles 323A and 323B of the Constitution of India with reference to judicial decisions.

(*b*) Critically examine the principle of Dicey's rule of law in the light of judicial decisions. 20

(*a*) न्यायिक विनिश्चयों के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 A और 323 B की सांविधानिक वैधता का विवेचन कीजिए।

(*b*) न्यायिक विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए डाइसी के विधिसम्मत शासन के सिद्धान्त की समीक्षात्मक जाँच कीजिए।

7. Can the absence of hearing before a decision is made be adequately compensated for, by post-decisional hearing ? Discuss referring to decided cases. 20

क्या विनिश्चयपूर्व सुनवाई की कमी की विनिश्चियोत्तर सुनवाई करके यथेष्ट रूप में प्रतिपूर्ति की जा सकती है ? विनिश्चित केसों को निर्दिष्ट करते हुए विवेचन कीजिए।

8. (*a*) When can a Writ of Mandamus be issued ?

(*b*) X, a public trust was running a college at Gandhinagar, affiliated to Gujarat university. The teachers were given the pay scale as recommended by the University Grants Commission. The teachers demanded the implementation of revised pay scales as recommended by University Grant Commission. The Chancellor directed all affiliated colleges to implement the revised pay scales. 'X', instead of revising the pay scales, closed the college and

terminated the services of teachers. The teachers made a representation to 'X' for grant of terminal benefits which they were entitled to as per law. 'X' refused to pay the same. The teachers filed a writ petition in high court. 'X' contended that high court cannot issue a writ, as it is not a statutory body. Decide with the help of judicial decisions. 20

(*a*) परमादेश रिट कब जारी की जा सकती है ?

(*b*) एक सार्वजनिक न्यास X गाँधीनगर में कॉलेज चला रहा था। जो गुजरात विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान दिया गया था। प्राध्यापकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथासंस्तुत परिशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन की माँग की। चांसलर ने सभी सम्बद्ध कॉलेजों को परिशोधित वेतनमानों पर अमल करने के निर्देश दिए थे। 'X' ने वेतनमान परिशोधित करने के बजाय कॉलेज ही

बन्द कर दिया और प्राध्यापकों की सेवाएँ समाप्त कर दीं। प्राध्यापकों ने X को उन सेवान्त प्रसुविधाओं को मंजूर करने के लिए अभ्यावेदन दिया जिनके वे विधित: हकदार थे। X ने उनका भुगतान करने से मना कर दिया। प्राध्यापकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की। X ने प्रतिवाद किया कि उच्च न्यायालय सांविधिक निकाय न होने के कारण रिट जारी नहीं कर सकता है। न्यायिक विनिश्चयों की सहायता से विनिश्चय कीजिए।